भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2889

बुधवार, दिनांक 05 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने हेतु

प्रधानमंत्री-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संतुष्टि का सर्वेक्षण

2889. श्री अरुण गोविल:

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान छत पर लगाए जाने वाली सौर ऊर्जा प्रणालियों के लिए प्राप्त आवेदनों की वर्ष-वार संख्या कितनी है और छत पर लगाए जाने वाले स्वीकृत और स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (पीएम-एसजीएमबीवाई) के कार्यान्वयन और इस योजना के संबंध में लाभार्थियों की संतुष्टि तथा जन जागरूकता को लेकर कोई अध्ययन/सर्वेक्षण कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत अब तक संस्थापित सोलर रुफटॉप की क्षमता कितनी है और उससे अनुमानित विद्युत उत्पादन कितना है;

(घ) क्या छत पर लगाए जाने वाली सौर ऊर्जा प्रणालियों की लागत कम हुई है और उपभोक्ताओं को किस समय-सीमा के भीतर राजसहायता संवितरित की जाती है;

(ङ.) क्या इस अवधि को और कम करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस योजना के अंतर्गत मेरठ-हापुड़ लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में संस्थापित छत पर लगाए जाने वाली सौर ऊर्जा प्रणालियों की संख्या कितनी है और प्राप्त शिकायतों की संख्या कितनी है और इन शिकायतों का निवारण किस प्रकार किया गया है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने मार्च 2019 में ग्रिड-कनेक्टेड रूफटॉप सोलर फेज़-II की शुरुआत की थी, जिसे बाद में फरवरी 2024 में शुरू की गई पीएम सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना (PMSG: MBY) में मिला दिया गया। दोनों योजनाएं मांग आधारित हैं और पिछले पांच वर्षों

अर्थात वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान इन योजनाओं के तहत कुल 33,28,814 रूफटॉप सोलर (RTS) सिस्टम लगाए जाने की सूचना है। वर्ष-वार विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	**स्थापित RTS सिस्टम (संख्या)**
2021-22	1,62,268
2022-23	1,51,192
2023-24	2,72,046
2024-25	8,72,724
2025-26	18,70,584

(ख) पीएमएसजीः एमबीवाई के कार्यान्वयन की समीक्षा राज्यों, DISCOMs और बैंकों के साथ विभिन्न स्तरों पर योजना की प्रगति की नियमित निगरानी के जरिए की जा रही है। उचित कदम उठाकर इसे लागू करने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए अलग-अलग हितधारकों से फीडबैक भी लिया जा रहा है। इसके अलावा, समय-समय पर क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें भी की जा रही हैं। इस योजना के तहत RTS लगवाने वाले ग्राहकों के बिजली बिल तो काफी कम हुए ही हैं, साथ ही, देश भर के DISCOMs ने सूचित किया है कि 18.93 लाख से ज़्यादा लाभार्थियों को अपनी बिजली की खपत के हिसाब से किसी भी महीने या बिलिंग साइकिल में शून्य बिजली बिल का लाभ मिला है।

इसके अतिरिक्त, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने देश भर में प्रमुख समाचार पत्रों में प्रिंट विज्ञापन, टीवी कमर्शियल, एफएम स्टेशनों और क्षेत्रीय चैनलों पर रेडियो अभियानों जैसे आउटरीच और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से इस योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए पहले ही उपाय किए हैं।

(ग) इस योजना के तहत, फरवरी 2024 में इसकी शुरुआत के बाद से, दिनांक 31.07.2026 तक कुल 14,653.23 मेगावाट क्षमता स्थापित की जा चुकी है।

ऐसा अनुमान है कि इस योजना के तहत एक करोड़ घरों में RTS लगाने से, RTS सिस्टम के 25 वर्षों के जीवनकाल में 1,000 बिलियन यूनिट नवीकरणीय बिजली का उत्पादन होगा।

(घ) और (ड): पीएमएसजी: एमबीवाई की शुरुआत के समय, 3 किलोवाट क्षमता वाले रूफटॉप सोलर (RTS) सिस्टम की बेंचमार्क लागत वर्ष 2016 में 75,000/- रुपये प्रति किलोवाट से कम होकर वर्ष 2024 में 50,000/- रुपये प्रति किलोवाट पीक (kWp) हो गई है। तथापि, इंस्टॉलेशन की वास्तविक लागत विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि उपयोग की जाने वाली सोलर PV तकनीक, साइट का स्थान और उसकी भौगोलिक स्थिति, आवश्यक लॉजिस्टिक्स, संरचना की ऊँचाई आदि।

पीएमएसजी: एमबीवाई योजना के अंतर्गत, आवेदन करने से लेकर केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) प्राप्त होने तक की संपूर्ण प्रक्रिया राष्ट्रीय पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध है। सब्सिडी का जल्द से जल्द भुगतान करने के प्रयास किए गए हैं। राष्ट्रीय पोर्टल पर सभी क्रेडेंशियल सही ढंग से दर्ज करने के बाद, उपभोक्ता द्वारा सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के अनुरोध किए जाने के लगभग 15 दिनों के भीतर CFA जारी कर दिया जाता है।

(च) इस योजना के अंतर्गत, फरवरी 2024 में इसके शुभारंभ से लेकर दिनांक 31.07.2026 की स्थिति के अनुसार, मेरठ-हापुड़ लोकसभा क्षेत्र में कुल 16,481 रूफटॉप सोलर (RTS) सिस्टम स्थापित किए जा चुके हैं।

पीएमएसजी: एमबीवाई के अंतर्गत, MNRE को सूचीबद्ध वेंडरों, सब्सिडी वितरण में देरी, नेट-मीटरिंग आदि के संबंध में कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं। समय पर समाधान के लिए ऐसी शिकायतों को संबंधित वेंडरों, DISCOMs और अन्य अधिकारियों के समक्ष उठाया जाता है।

*****